डॉली चांडा

बनाम

अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य

5 अक्टूबर, 2004

[आर. सी. लाहोटी, सीजे जी. पी. माथुर और प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर, जे. जे.]

शिक्षाः

मेडिकल कॉलेज में उच्च शिक्षा प्रवेश-आरक्षित श्रेणी में- प्रमाण पत्र में गलती के कारण अयोग्यता के कारण प्रवेश से इनकार- गलती के सुधार के बावजूद उम्मीदवार पर विचार नहीं किया गया-रिट याचिका- खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित की गईः प्रवेश से इनकार करना अन्यायपूर्ण और अवैध है-सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार को उसके देय से वंचित नहीं किया जा सकता है-प्रमाण प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है-उम्मीदवार को प्रवेश देने का निर्देश।

अपीलार्थी 2003 में आरक्षित एम. आई. श्रेणी के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूर्व सैनिक की बेटी थी जिसे स्थायी विकलांगता के आधार पर सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें परामर्श के लिए बुलाया गया था।

जांच में यह पता चला कि जिला सैनिक बोर्ड द्वारा उनके पिता को दिया गया प्रमाण पत्र आरक्षित एमआई श्रेणी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता था, और उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने सेना अधिकारियों द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और परामर्श के एक और दौर के समय गलती को सुधारने के बाद जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी नया प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की कि यह सही प्रमाण पत्र जारी नहीं करने में सैनिक बोर्ड की गलती थी, और इसे दूसरे प्रमाण पत्र में ठीक किए जाने के कारण, वह प्रवेश की हकदार थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह प्रवेश की हकदार नहीं थी क्योंकि उसका यह दावा कि वह आरक्षित एमआई श्रेणी से संबंधित थी, पहली परामर्श के समय स्थापित नहीं किया गया था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अपीलार्थी निस्संदेह आरक्षित एम. आई. श्रेणी से संबंधित था। हो सकता है कि उसके पिता ने पहला प्रमाण पत्र जारी करते समय जिला सैनिक बोर्ड द्वारा की गई गलती पर ध्यान न दिया हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब अपीलार्थी ने दूसरे परामर्श के चरण में सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो उसे उसके देय से वंचित कर दिया जाना

चाहिए। अपीलार्थी के प्रवेश से इनकार करने में अधिकारियों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अवैध है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में राज्य के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में अपीलार्थी को तुरंत प्रवेश दें। यदि राज्य की सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं तो उनके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाएगी। [84-जी-एच; 85-ए; 85-सी]

2. आरक्षण या वेटेज आदि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। ये विशेष योग्यता या सुरक्षित अंकों का प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता रखने के प्रमाण की प्रकृति के दस्तावेज हैं। किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, सबूत प्रस्तुत करने के मामले में कुछ ढील दी जा सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। [83-ए-बी]

चार्ल्स के. स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य, [1980] 2 एससीसी 752 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2004 की सिविल अपील सं. 6506

2003 की डबल्यू.पी. संख्या 11248 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 31.10.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से अमरेंद्र बल और राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय।

उत्तरदाताओं के लिए जनारंजन दास, श्वेतकेतु मिश्रा और सुश्री मौसमी गहलोट।

न्यायालय का निर्णय दिया गया,

जी.पी. माथुर

1. अनुमति दी गई

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थियों को उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश जारी करने के लिए दायर रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलार्थी ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, उड़ीसा द्वारा आयोजित 10+2 (विज्ञान) परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। चूंकि वह एक चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल होने की इच्छुक थी, इसलिए वह एक पूर्व सैनिक एन. के. मनोरंजन छांडा, जिन्हें स्थायी विकलांगता के आधार पर सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई थी की बेटी के रूप में आरक्षित एम. आई. श्रेणी के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2003 (संक्षिप्त रूप से 'जे. ई. ई.-2003' के लिए) में उपस्थित हुई, । जे. ई. ई.-2003 के सूचना विवरणिका

के खंड 2.1.4 के तहत कुछ प्रतिशत सीटें उड़ीसा के सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षित हैं, जो युद्ध या शांति अभियान के दौरान कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हैं। मेडिकल स्ट्रीम में आरक्षित एम. आई. श्रेणी में जे. ई. ई.-2003 में उनकी रैंक 20 थी और तदनुसार उन्हें 7.7.2003 पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए परामर्श के लिए बुलाया गया था। कागजातों की जांच के दौरान यह पता चला कि कॉलम संख्या 3 में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा उनके पिता को दिए गए दिनांकित 29.6.2003 प्रमाण पत्र में "विकलांग/युद्ध/शत्रुता में मारे गए" से संबंधित शब्द "अयोग्य" लिखे गए थे। चूंकि उपरोक्त प्रमाणपत्र आरक्षित एम. आई. श्रेणी की आवश्यकता को पूरा नहीं करता था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था। जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्त श्रेणी में 24 और 26 रैंक हासिल किए थे, उन्हें प्रवेश दिया गया था। उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो सेना के अधिकारियों द्वारा उनके पिता को जारी किया गया था, लेकिन सूचना विवरणिका के खंड 2.1.4 की आवश्यकता को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अपीलार्थी के पिता ने तब जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर से गलती को सुधारने का अनुरोध किया, जिसने 16.7.2003 पर एक नया प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कॉलम संख्या 3 में "स्थायी रूप से अक्षम" का उल्लेख किया गया था। अपीलार्थी फिर से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास गया और कहा की मेरे पास उपरोक्त सही प्रमाण पत्र है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की

गई। यह जानने पर कि सीट में वृद्धि के कारण 29.10.2003 के लिए परामर्श का एक और दौर तय किया गया था, अपीलार्थी संबंधित केंद्र में गया और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश देने का अनुरोध किया, जो प्रमाणित करता है कि उसके पिता को स्थायी विकलांगता के आधार पर सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई थी। एमआई श्रेणी में 27 से 30 तक रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाया गया था, लेकिन अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया था। अपीलार्थी का मामला इस प्रकार है कि यह जिला सैनिक बोर्ड ही था जिसने सही प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की गलती की थी और उक्त गलती को 16.7.2003 पर जारी दूसरे प्रमाण पत्र में ठीक किया गया था, वह एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए हकदार थी क्योंकि निम्न रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पहले ही भर्ती कराया जा चुका था।

4. अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 7.7.2003 पर परामर्श के समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में इस बात की कोई गवाही नहीं थी कि उसके पिता उड़ीसा के सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों के कर्मी होने के नाते कार्रवाई में अक्षम हुये थे और परिणामस्वरूप सूचना विवरणिका के खंड

2.1.4 के संदर्भ में उसका दावा कि वह आरक्षित एम. आई. श्रेणी से संबंधित है, स्थापित नहीं किया गया था।

5. प्रत्यर्थियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी ने आरक्षित एम. आई. श्रेणी में जे. ई. ई.-2003 में मेडिकल स्ट्रीम में क्रम 20 रैंक हासिल की थी। लिया गया रुख यह है कि 7.7.2003 पर परामर्श के समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं था कि उसके पिता सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों के विकलांग कर्मी थे, उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि उनकी अयोग्यता के कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी, इसलिए उन्हें दूसरी परामर्श में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह तथ्य विवादित नहीं है कि आरक्षित एम. आई. श्रेणी में अपीलार्थी से कम रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है।

6. अपीलार्थी ने सिग्नल अभिलेख कार्यालय, सिग्नल्स रिकॉर्ड्स, पोस्ट बैग नंबर 5, जबलपुर (एम. पी.) द्वारा जारी दिनांकित 3.10.2001 प्रमाण पत्र की एक प्रति दाखिल की है, जो प्रमाणित करता है कि वी. पी. ओ. लारम्बा, जिला संबलपुर (उड़ीसा) के पूर्व-एन. के. मनोरंजन छांडा निवासी स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं। 7.7.2003 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड द्वारा 28.6.2003 पर जारी किया

गया था और इस प्रमाण पत्र में एक गलती हो गई थी, अर्थात् कॉलम संख्या 3 में "युद्ध/शत्रुता में विकलांग/मारे गए" से संबंधित, "पात्र नहीं" शब्द लिखे गए थे। इस गलती को जिला सैनिक बोर्ड द्वारा 16.7.2003 पर जारी किए गए दूसरे प्रमाण पत्र में सुधार किया गया था, जहां कॉलम संख्या 3 में "स्थायी रूप से अक्षम" शब्द लिखे गए थे। तथ्यात्मक स्थिति, अर्थात्, कि अपीलार्थी के पिता मनोरंजन छंदा को स्थायी विकलांगता के कारण सेना से छुट्टी दे दी गई थी, उत्तरदाताओं द्वारा बिल्कुल भी विवादित नहीं है। इसी तरह, जिला सैनिक बोर्ड, संबलपुर द्वारा जारी किए गए दूसरे प्रमाण पत्र की शुद्धता, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पूर्व एन. के. मनोरंजन छांडा को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा था, भी विवादित नहीं है। एकमात्र आधार जिस पर अपीलार्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था, वह यह है कि 7.7.2003 को परामर्श के समय वह यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही कि वह एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है।

7. सामान्य नियम यह है कि अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समय, किसी व्यक्ति के पास प्रवेश विवरणिका में या आवेदन पत्र में, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है,

अर्थात निर्धारित तिथि तक अपेक्षित पात्रता रखने के मामले में। इसे आवश्यक प्रमाण पत्र, डिग्री या अंकपत्र प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना है। इसी तरह, आरक्षण या वेटेज आदि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। ये विशेष योग्यता या सुरक्षित अंकों का प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता रखने के प्रमाण की प्रकृति के दस्तावेज हैं। किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, सबूत जमा करने के मामले में कुछ ढील दी जा सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

8. इस सिद्धांत को चार्ल्स के स्कारिया और अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू और अन्य, [1980] 2 एससीसी 752 में समझाया और लागू किया गया था। यहाँ विवाद चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित है। यदि किसी उम्मीदवार के पास संबंधित विषय या उप-विशेषज्ञता में डिप्लोमा है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त नंबर का लाभ दिया जाएगा और यह लाभ केवल तभी दिया जा सकता है जब डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उम्मीदवार की सफलता को चयन समिति के संज्ञान में प्रामाणिक या स्वीकार्य तरीके से चयन पूरा करने से पहले लाया जाए। विवरण पत्रिका ने प्रावधान किया कि प्रत्येक आवेदन के साथ अंकों के

विवरण और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। ऐसे तीन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया जिन्होंने अपने आवेदनों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। उच्च न्यायालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उनके आवेदन, जिसमें उन्होंने डिप्लोमा के लाभ का दावा किया था, अस्वीकार किए जाने योग्य थे क्योंकि आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए गए थे। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से बोलते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश देना सही था क्योंकि उन्होंने वास्तव में निर्धारित तिथि से पहले डिप्लोमा पास कर लिया था। निर्णय के पैरा 20 और 24 के प्रासंगिक भाग, जहाँ इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया था, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैंः

> "20. डिप्लोमा धारकों के लिए 10 अंक जोड़ने में कुछ भी अनुचित या मनमाना नहीं है। लेकिन इन अतिरिक्त 10 अंकों को अर्जित करने के लिए, डिप्लोमा कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, बाद में नहीं। डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण इसे प्राप्त करने के तथ्य से अलग है। क्या वास्तव में उम्मीदवार ने डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की

अंतिम तिथि से पहले डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है? यही मुख्य प्रश्न है। आवेदन के साथ डिप्लोमा का प्रमाण प्रस्तुत करना विवेकपूर्ण है, लेकिन यह गौण है। पहले दिन तिथि में ढील देना अवैध है, दूसरे दिन ऐसा नहीं है। एक डिप्लोमा के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता, जिसके लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रमाण केवल बाद में प्रस्तुत किया जाता है, फिर भी वास्तविक चयन की तारीख से पहले। डिप्लोमा पर जोर दिया जाता है; इसका प्रमाण डिप्लोमा के कब्जे के तथ्य को कम करता है और यह एक स्वतंत्र कारक नहीं है। प्रमाण का तरीका विचाराधीन योग्यता के लक्ष्य के लिए तैयार किया जाता है। यह दोनों को एकदूसरे मे मिलाने और समय के साथ दोनों को अनिवार्य बनाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ध्वनि व्याख्या और यथार्थवादी डिकोडिंग का विध्वंसक है। जो आवश्यक है वह दी गई तारीख से पहले एक डिप्लोमा का कब्जा है; जो सहायक है वह योग्यता के प्रमाण का सुरक्षित तरीका है। किसी तथ्य और उसके प्रमाण के बीच भ्रमित होना अस्पष्ट समझदारी है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि से पहले अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की तारीख को अनिवार्य बनाना समझ में आता है। लेकिन अगर यह

अडिग रूप से दिखाया जाता है कि योग्यता को प्रासंगिक तिथि से पहले प्राप्त किया गया है, जैसा कि यहां मामला है, तो इस योग्यता कारक को अमान्य करने के लिए क्योंकि प्रमाण, हालांकि निर्विवाद है, कुछ दिनों बाद लेकिन चयन से पहले या इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण पत्रिका में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के ऊपर, प्रक्रिया को नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन और रूप को सार के अधीन नहीं बल्कि सार से बेहतर बनाना है।

24. यह कुख्यात है कि यह औपचारिक, अनुष्ठानवादी, दृष्टिकोण अवास्तविक है और अनजाने में दर्दनाक, अन्यायपूर्ण और अभ्यास के उद्देश्य के लिए विध्वंसक है। समस्याओं को देखने का यह तरीका प्रशासनिक, न्यायिक और यहां तक कि विधायी प्रक्रियाओं को मानव के लिए कानून के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अमानवीय बनाता है न कि कानून के लिए मानव। प्रशासन में अधिकांश कठिनाई और उत्पीड़न आवश्यक के बजाय बाहरी पर अधिक जोर देने से होता है। हमारा मानना है कि सरकार और चयन समिति ने डिप्लोमा रखने को साबित करने के तरीके को निर्देशिका

(अनिवार्य नहीं) और डिप्लोमा के वास्तविक कब्जे को अनिवार्य माना। वास्तविक जीवन में, हम जानते हैं कि डिग्री, फरमानों और विलेखों की प्रतियां प्राप्त करना, विश्वविद्यालयों से अंक-सूची जैसे अन्य प्रमाणित दस्तावेजों की बात नहीं करना, क्यों, यहां तक कि अदालतों से जमानत के आदेश और सार्वजनिक कार्यालयों से सरकारी आदेश प्राप्त करना कितना अत्यधिक विलंबकारी है।"

9. अपीलार्थी निस्संदेह आरक्षित एम. आई. श्रेणी से संबंधित थी। वह एक बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आती हैं, उनके पिता सशस्त्र बलों में केवल एक नायक थे। हो सकता है कि उन्होंने उस गलती पर ध्यान न दिया हो जो जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिनांक 29.6.2003 का पहला प्रमाण पत्र जारी करते समय की गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब अपीलार्थी दूसरी परामर्श के चरण में सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे उसके देय से वंचित कर दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपीलार्थी से कम रैंक हासिल की है, उन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है। अपीलार्थी के प्रवेश से इनकार करने में अधिकारियों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अवैध है।

10. अपीलार्थी ने जे. ई. ई.-2003 में अर्हता प्राप्त की थी लेकिन उक्त शैक्षणिक वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इस स्थिति के

लिए दोष उत्तरदाताओं का है, जिन्होंने अत्यधिक तकनीकी और कठोर रवैया अपनाया, न कि अपीलार्थी का। इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थी को चालू शैक्षणिक वर्ष में किसी भी राज्य के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

11. तदनुसार अपील की अनुमति लागत के साथ दी जाती है। उच्च न्यायालय के 31.10.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तुरंत प्रवेश दें। यदि राज्य की सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं, तो उनके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाएगी।

के. के. टी. अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।